माननीय न्यायमूर्ति *जसबीर सिंह और* ***न्यायमूर्ति*** *ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह* ***के समक्ष***

मैसर्स भनोट लीजिंग लिमिटेड और अन्य - ***पेड़टियोनर्स***

बनाम

आयुक्त, गु आरगांव डिवीजन

गुड़गांव और अन्य -*प्रतिवादी*

1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821

6 अक्टूबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1961-धारा 2 (जी) और 13-ए-भूमि - मालिकों के कब्जे को दर्शाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में शामलात देह के रूप में दर्ज भूमि- भूमि मालिकों के पक्ष में मुकदमा दायर करने वाले सहायक कलेक्टर ने भूमि मालिकों के पक्ष में मुकदमा दायर किया- ***कलेक्टर ने ग्राम पंचायत की अपील को खारिज कर दिया- भूमि खरीदने वाले याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नामांतरण की मंजूरी- ग्राम पंचायत द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करना- पक्षों की सुनवाई के बाद आयुक्त ^(§) में प्रावधान है कि गांव के कुल क्षेत्रफल के 25% से अनधिक भूमि शामलात देह के रूप में ग्राम पंचायत में निहित हो सकती है। (1(5) से (5) - आयोजित, सं- उप सीआईएस। (छ) की धारा 2(छ) के खंड (1) से (5) एक दूसरे से स्वतंत्र हैं- 1961 के अधिनियम में संशोधन उपखंड (5) के परंतुक को हटाना (5) पुनरीक्षण कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान-क्या ऐसे संशोधन पर विचार किया जा सकता है-आयोजित, हां-पुनरीक्षण पेटिटीमूल वाद की निरंतरता है-स्वामित्वकर्ता या बाद के क्रेता किसी राहत के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनका दावा केवल उपखंड (5) के परंतुक पर आधारित है।***

यह माना जाता है कि प्रासंगिक समय पर 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) का अवलोकन करने से पता चलता है कि जब मूल भूमि मालिकों ने धारा 13-ए के तहत मुकदमा दायर किया था, तो यह दिखाएगा कि शामलात देह की परिभाषा राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित भूमि को शामिल करने के साथ शुरू होती है जैसा कि उप-खंड (1) से (5) में प्रदान किया गया है। उपखंड (5) के पश्चात्, परंतुक रखा गया है। पीरोविसो के बाद, उन जमीनों का बहिष्कार शुरू होता है जो शामलात देह में शामिल नहीं हैं। धारा 2 (जी) परिभाषित करती है

शामलात देह का उपखंड (1) से (5) में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणियों को शामिल कियाजाना तत्पश्चात् उपखंड (5) में इस आशय का परंतुक जोड़ा जाता है किगांव के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 25% गांव में मौजूद नहीं है। यदि यह परंतुक सभी उप-खंडों पर लागू होता, तो इसे अपवर्जन खंडों में शामिल किया जाता जो धारा में परंतुक का पालन करते हैं। 1991 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 (बी) के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि 1961 के अधिनियम में शामिल परंतुक केवल धारा 2 (जी) के उपखंड (5) के लिए था।

(पैरा 19 और 21)

मेसर्स भनोट लीजिंग लिमिटेड और ओटियर्स वी। टी 1 आईई आयुक्त। 259
गुड़गांव डिवीजन गुड़गांव और अन्य
(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।

आगे कहा गया कि भूमि शामलात देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है और जमाबंदी में प्रविष्टि है कि भूमि शामलात देह है, लेकिन खेवट में संबंधित हिस्से के अनुसार मालिकों के कब्जे में भूमि की प्रकृति से विचलित नहीं होती है और भूमि का चरित्र शामलात देह रहता है। **शिव चारण सिंह** और अन्य बनाम ग्राम **पंचायत, नारिके** और अन्य, 1977 पीएलजे 453 और **तेल राम** और अन्य *बनाम* **ग्राम सभा मानकपुर और अन्य,** 1976 पीएलजे 628 में इस न्यायालय के इवो डिवीजन बेंच के निर्णयों ने माना है कि धारा 2 (जी) के सभी उप-खंड एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और शासन या परिधि नहीं करते हैंकिसी भी तरह से एक दूसरे के दायरे को लिखें। यह अधिनियम की धारा 2 (जी) के केवल उप-खंड (5) पर लागू होने वाले परंतुक के संबंध में हमारे द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को और मजबूत करता है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि परंतुक धारा 1961 के अधिनियम के उपखंड (5) पर लागू होता है। केवल 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) के उपखंड (1) से (4) के लिए नहीं।

इसके अलावा, यह माना गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। यदि क़ानून किसी भी सीमा के लिए प्रदान नहीं करता है, तो न्यायालय ऐसी अवधि को अपने दम पर आयात नहीं कर सकता है। आयुक्त *स्वतः प्रेरणा* से अपनी दूरदर्शी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान मामले में, कलेक्टर द्वारा दिनांक 131 दिसंबर, 1988 के आदेश के पारित होने के बाद, 21 जुलाई, 1989 को ग्राम पंचायत द्वारा संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी, आयुक्त द्वारा उसी का मनोरंजन बिना किसी अधिकार क्षेत्र के शक्तियों की सीमा या विस्तार से परे नहीं कहा जा सकता है।

(26 में कार्य करता है)

आगे कहा गया कि मूल कार्यवाही तब तक जारी रहती है जब तक कि यह धारा 13-सी के तहत प्रदान की गई अंतिम तिथि प्राप्त नहीं कर लेती। 1961 अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही इस प्रकार, मूल कार्यवाही की निरंतरता होगी। 1961 के अधिनियम में संशोधन1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा 11 फरवरी को हरियाणा के राज्य द्वारा लाया गया था। 1992. 1991 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 (बी) उप-क्लॉस्क (5) के परंतुक का लोप किया गया है।

(30 परोसता है)

आगे कहा गया कि पुनरीक्षण आयुक्त के समक्ष लंबित था जब 1961 का अधिनियमसमाप्त हो गया था। आयुक्त ने संशोधन का निर्णय लेते समय 1961 के अधिनियम में संशोधन पर सही ध्यान दिया है। इस प्रकार, 1961 अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही मूल वाद की निरंतरता है। धारा 2 (जी) में संशोधन आरसीविसियो एनएएल कार्यवाही पर लागू होगाऔर चूंकि यह मूल कार्यवाही की निरंतरता है, निहित अधिकार, यदि बाद के खरीदारों में से कोई भी सिद्धांत द्वारा मारा जाएगा, तो वे मूल भूमि मालिकों यानी गांव के मालिकों से बेहतर शीर्षक का दावा नहीं कर सकतेहैं।

(32 में कार्य करता है)

एम.एल. सरीन। मैं इकमान सरीन के साथ सीनियर एडवोकेट। एडवोकेट, सुवीर सहगल। एडवोकेट और एस.आई. भल्ला। 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 और 1996 के 2069 में याचिकाकर्ताओं के वकील।

(एमटी गोयल। 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10381 में याचिकाकर्ता के लिए वकील।

कमल सहगल। अतिरिक्त ए.जी. 1 किरयाना। आशीष अग्रवाल। एडवोकेट और जे.एस. अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, एक्स

(1) इस आदेश से, हम तीन रिट याचिकाओं यानी 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 **मेसर्स भनोट लीजिंग लिमिटएड** और अन्य *बनाम* **आयुक्त, गुड़गांव डिवीजन, गुड़गांव और अन्य,** 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2069 पर फैसला करने का प्रस्ताव करते हैं।**मैसर्स डिसेंट लोअर** (पी) लिमिटेड और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य जिसमें आदेश दिनांक 23 जुलाई को हरियाणा **राज्य और अन्य** शामिल हैं। 1992 (अनुबंध पी-7) आयुक्त द्वारा पारित किया गया। गुड़गांव डिवीजन। गुड़गांव को चुनौती दी गई है और 1989 ग्राम पंचायत संख्या 10381,

रितोज *बनाम* आयुक्त **(अपील) अंबाला मंडल और अन्य**, जिसमें आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1989 (अनुबंध पी-3) को रद्द कर दिया गया है।

(2) पक्षकारों के वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि इन रिट याचिकाओं को एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा सकता है क्योंकि समान तथ्य और कानून के समान प्रश्न शामिल हैं। 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 और 1996 की 2069 में तथ्य इस प्रकार हैं: -

(3) इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने गांव बेहरामपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के मालिकों से जमीन खरीदी। विचाराधीन भूमि वर्ष 1939-40 के राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में देह *हास आह रा साद राखा ज़मीन* में शा एमएल के रूप में दर्ज की गई है और खेती के स्तंभ में, मालिकों को खेती के कब्जे में दिखाया गया है। भूमि मालिकों ने सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रतिवादी-ग्राम पंचायत, ग्राम बहरामपुर के खिलाफ पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 13-ए के तहत एक मुकदमा दायर करके भूमि के स्वामित्व के अपने अधिकार का दावा किया। 1 सेंट ग्रेड, गुड़गांव। उक्त वाद में, यह प्रार्थना की गई थी कि इस आशय की घोषणा जारी की जाए कि वेभूमि के कब्जे में मालिक थे और ग्राम पंचायत का इसमें कोई निहित अधिकार नहीं था। वाद की डिक्री भूमि स्वामियों के पक्ष में 20 जून, 1988 के आदेश (अनुबंध पी-1) *द्वारा* की गई थी।

(4) प्रतिवादी-ग्राम पंचायत ने कलेक्टर, गुड़गांव के समक्ष सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने 13 दिसंबर, 1988 के आदेश (अनुबंध पी-2) द्वारा इसे खारिज कर दिया। प्रतिवादी-ग्राम पंचायत द्वारा तुरंत कोई संशोधन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपील की घोषणा और खारिज होने के बाद, 24 जनवरी, 1989 से 7 अप्रैल, 1989 की अवधि के दौरान विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम से भूमि खरीदी। 17 जुलाई, 1989 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किया गया था।

(5) प्रतिवादी-ग्राम पंचायत ने 21 जुलाई, 1989 को आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने दिनांक 21 जुलाई, 1989 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) द्वारा 20 जून के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। 1988 सहायक कलेक्टर, प्रथम ग्रेड, गुड़गांव और कलेक्टर द्वारा पारित किया गया, गुड़गांव दिनांक 31 दिसंबर को। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1988 के आदेश के तहत 1988 में एक याचिका दायर की थी और उक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों को और रोक दिया गया था

भूमि के चरित्र को बदलने से लेकर या विदेशी नेउसी को खाया या अगले आदेश तक किसी भी तरह से इसकी प्रकृति को बदलने के लिए। चूंकि, याचिकाकर्ताओं को पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए ग्राम चरण द्वारा याचिकाकर्ताओं को पक्षकार के रूप में अभिवादन करने के लिए एक आवेदन (अनुलग्नक पी-5) को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि वेकलेक्टर के दिनांक 31 दिसंबर, 1988 के निर्णय के बाद बाद के खरीदार थे। उक्त आवेदन को आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई थी और

याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे जो आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए और पुनरीक्षण याचिका पर अपना जवाब छिपाया औरअपने लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए- अनुबंध पी-6 के *माध्यम से*। आयुक्त ने पक्षों को सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दे दी। 1992 (अनुलग्नक पी -7), ग्राम पंचायत द्वारा पसंद किया गया, जिसमें भूमि मालिकों के पक्ष में पारित आदेशों को रद्द करते हुए कहा गया था कि 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के बाद दिखाई देने वाला परंतुक, जो शामलात देह को परिभाषित करता है, यह केवल उपखंड (5) पर लागू होता है न कि उपखंड (1) से (5) में उल्लिखित कुल शामलात देह भूमि पर। आगे यह माना गया कि 11 फरवरी, 1992 से अधिनियम में लाए गए संशोधन को उप-धारा (5) के प्रावधान को हटाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि आसानी को समाप्त नहीं कहा जा सकता है और पुनरीक्षण याचिका मूल वाद की निरंतरता है। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष इन दो रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

(6) 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10381 में। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने विशेष कलेक्टर के समक्ष धारा 13-एओएफएलएचसी पंजाब विलेजकॉमन 1 और (विनियमन) अधिनियम 1961 के तहत मुकदमा दायर किया। पहली कक्षा। गुड़गांव को यह घोषणा करने के लिए कि विवादित भूमि शाम *आई अल देह की* परिभाषा के भीतर नहीं आती है, जैसा कि 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, डॉक्टर ग्राम पंचायत में निहित नहीं हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 (गांव के मालिक) के खिलाफ दर्ज जमाबंदी में इस आशय की प्रविष्टियां गलत हैं। उक्त वाद को विशेष कलेक्टो आर. प्रथम श्रेणी द्वारा खारिज कर दिया गया था। गुड़गांव—दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के आदेश के तहत (संलग्नक पी-1)।

(7) प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने जिला कलेक्टर के समक्ष अपील की। गुड़गांव। जिसने भी उक्त अपील को खारिज कर दिया.-*आदेश* दिनांक 261 अगस्त, 1986 (अनुबंध पी-2) द्वारा ग्राम पंचायत को भूमि का मालिक माना जाता है। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने आयुक्त (अपील) के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। अंबाला मंडल,

नहीं तो

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24 फरवरी, 1989 के आदेश (अनुबंध पी-3) *द्वारा* यह टिप्पणी करने के बाद कि 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) के उपखंड (5) के अंत में दिया गया परंतुक न केवल उपखंड (5) पर बल्कि इस धारा के उपखंड (1) से (4) पर भी लागू होता है और तदनुसार यह निर्णय दिया कि भूमि कुल क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है (ग) ग्राम पंचायत में शमलत देह के रूप में 5000 वर्ग किमी ग्राम का प्रावधान किया जा सकता है। उक्त आदेश को इस रिट याचिका में ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

(8) इस प्रकार, 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के बाद प्रदान किए गए परंतुक की प्रयोज्यता के संबंध में रिट याचिकाओं के इन दो सेटों में दो व्याख्याएं सामने आई हैं। यहां यह उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 टीम के एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, जिन्होंने इस मामले को निर्णय के लिए डिवीजन बेंच को संदर्भित किया था। दिनांक 26 मार्च, 2009 का संदर्भ आदेश निम्नानुसार है-

> "याचिकाकर्ताओं के अधिकार के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बाद के खरीदार हैं और धारा 2 (जी) के तहत खंड (5) के तहत परंतुक की प्रयोज्यता के रूप में केवल आयुक्त द्वारा आयोजित किया गया है, इस मामले में उठता है। यह भी तय किया जाना है कि क्या संशोधन मूल वाद की निरंतरता है। यह उचित होगा

कि इन सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को खण्ड न्यायपीठ के समक्ष रखा जाए।

मामले को खण्ड न्यायपीठ के समक्ष रखने और न्यायपीठ के गठन के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखे जाएं।

(9) इस प्रकार ये रिट हमारेसमक्ष अधिनिर्णय के लिए आए हैं।

(10) श्री सरीन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते हैं कि 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के प्रावधान बताते हैं कि प्रत्येक उप-खंड (1) से (4) अर्धविराम के साथ समाप्त होता है जबकि उप-खंड (5) एक कोलन के साथ समाप्त होता है। यह इंगित करता है कि खंड (1) से (5) का पाठ उप-खंड (5) के साथ समाप्त होता है। परंतुक एक अलग पैराग्राफ में सन्निहित है और शब्द 'प्रोविसो' के लिए एक बड़े शब्द 'पी' से शुरू होता है। उप-खंड (5) और अपवादों के बीच के परंतुक आंकड़े "औरइसमें भूमि शामिल नहीं है ..."। फाई, इस आधार पर, तर्क देता है कि परंतुक सभी उप-खंडों पर लागू होता है, अर्थात (1) से

(5). उनका तर्क है कि जब तक यह दिखाने के लिए कोई विशेष संकेत नहीं है कि किसी धारा का परंतुक केवल उसके एक भाग तक ही सीमित है, और न हीपरंतुक पूरे खंड को नियंत्रित करता है। अपवाद के रूप में प्रत्येक खंड के बाद इसे दोहराने के लिए पूरे खंड पर लागू होने वाले परंतुक बनाने के उद्देश्य से आवश्यक नहीं है। इस तर्क के समर्थन में, वह मद्रास प्रथम लीग कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करता है जो **कि शारदाम्हाल रे/अवशेतालक्ष्मी,** (1) की सहजता में है। मैं आगे यह निवेदन करता हूं कि अधिनियम की धारा 4 और 5 उस स्थिति को और स्पष्ट करती है जो पंचयालों में निहित या निहित मानी गई भूमि के उपयोग और कब्जे आदि के अधिकार निहित और गैर-स्वामित्वकर्ताओं को अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। 1 आगे विवाद यह है कि 1961 के अधिनियम में संशोधन किया गया - पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट के तहत, हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1991 (इसके बाद संशोधन अधिनियम, 1991 के रूप में संदर्भित) हरियाणा राज्य,- -1992 का अधिनियम संख्या 9 भावी है और इसलिए, भूमि मालिकों या बाद के खरीदारों के निहित अधिकारों को नहीं छीन सकता है। इस विवाद के समर्थन में, वह **K. Eapen Chako** *बनाम* **The Provident Investment Company (P.) Ltd., (2)** की आसानी में I lon'blc सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर निर्भर करता है।संशोधन प्रावधान i.c. धारा 2 (बी) के संबंध में- जिसके परंतुक को संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा छोड़ दिया गया है, वह तर्क देता है कि उक्त प्रावधान केवल परंतुक की जगह को दर्शाता है और यह इंगित नहीं करता है कि परंतुक केवल 1961 अधिनियमकी धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के लिए था।

(11) विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करता है कि पुनरीक्षण मूल वाद की निरंतरता नहीं है और इसलिए, हरियाणा राज्य द्वारा 1961 के अधिनियम में लाया गया संशोधन। उक्त कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सका। इस तर्क के समर्थन में, वह **मेसर्स राम सरन दास तारा ('हाथ** *बनाम* **राम रिछपाल और अन्य, (3)** के मामले में इस क्लॉर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हैं।

(12) प्रति कॉन्ट्रा। श्री अग्रवाल, प्रतिवादी-क्रैम पनेहयात के वकील। प्रस्तुत करता है कि जमाबंदी में शामलात देह के रूप में दर्ज की गई भूमि भले ही खकवाई में उनके संबंधित शेयरों के अनुसार मालिकों के कब्जे में दिखाई गई हो। डॉक्स भूमि की प्रकृति से अलग नहीं होते हैं क्योंकि वही शामलात देह है। उनके द्वारा (I) एआईआर 1962 मद्रास 108 (2) एआईआर 1976 एससी 2610 (3) 1961 (2) आईएलआर (पीबी) 507 पर भरोसा किया गया है

सुखदेव सिंह और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, **ग्राम सभा, बारी खड्ड** और अन्य, (4) और **शिव चरण**

सिंह और अन्य बनाम ग्राम **पंचायत, नारिके और अन्य** बनाम इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर, (5)। वह प्रस्तुत करता है कि अधिनियम की धारा 2 (जी) के सभी उप-खंड एक-दूसरे पर निर्भर हैं और किसी भी तरह से एक-दूसरे के दायरे को नियंत्रित या सीमित नहीं करते हैं। परंतुक उप-क्लॉस्क (5) के बाद रखा गया है और इसलिए, केवल उस उप-क्लॉस्क पर लागू होता है। मैं आगे यह भी तर्क देता हूं कि संशोधन अधिनियम, 1991 के *माध्यम से* हरियाणा राज्य द्वारा लाया गया संशोधन किसी भी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ता है कि परंतुक केवल उप-क्लॉज (5) के लिए था। वह इस अधिनियम की धारा 2 (बी) का उल्लेख करता है।

(13) श्री सरीन के इस तर्क का खंडन करते हुए कि संशोधन धारा की निरंतरता नहीं है,श्री अग्रवाल, विद्वान वकील, प्रस्तुत करते हैं कि 1961 का अधिनियम स्वयं अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत संशोधन का प्रावधान करता है। वह धारा 13-Coflhc 1961 Actio को संदर्भित करता है कि कॉमि सियोनर द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगाक्योंकि इस तरह के आदेश के खिलाफ इस अधिनियम के तहत कोई और उपाय प्रदान नहीं किया गया है। यह एक वैधानिक अधिकार है और इसलिए यह वाद को जारी रखना होगा। इस तर्क के समर्थन में, वह **ग्राम सबए, सलीना** *बनाम* **नाहर सिंह और अन्य** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हैं, (6) जिसमें यह माना गया है कि न्यायालय कानून में बदलाव का नोटिस केवल तभी ले सकता है जब कार्यवाही राजस्व अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की निरंतरता में हो। उन्होंने **बचना @ बचन सिंह** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य, (7)** में इस न्यायालय के न्यायाधीश पर भी भरोसा किया है।वह प्रार्थना करता है कि याचिका खारिज कर दी जाए।

(14) हमने पार्टियों के वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ आसानी के रिकॉर्ड के माध्यम से गए हैं ।

(15) वर्तमान में निर्णय के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे सहज हैं-

(1) क्या 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) के उप-क्लॉस्क (5) के बाद रखा गया प्रावधान उप-खंड (1) से (5) पर लागू होता है या केवल उप-क्लॉस्क (5) पर लागू होता है?

(4) 19771'0750
(5) 1977 पी.यू. 453
(6) I982 पी.एलजे.261
(7) 1986 पी.एल.जे. 83

(2) क्या पुनरीक्षण वाद की निरंतरता है या नहीं?

(3) यदि हां, तो क्या 1961 के अधिनियम में संशोधन अधिनियम, 1991 के तहत लाया गया संशोधन अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही और उसके प्रभाव को उन सभी पक्षों के निहित अधिकारों पर लागू करता है?

प्रश्न 1 का उत्तर :

(16) प्रासंगिक समय पर 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) जब मूल भूमि मालिकों ने धारा 13-ए के तहत मुकदमा दायर किया, इस *प्रकार* है : -

(17) **परिभाषाएँ--**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से

(छ) "शाम्लत देह" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(1) राजस्व अभिलेखों में वर्णित भूमि शामलात देह या चारंद आबादी देह को छोड़कर;

(2) शामलात सीढ़ी;

(3) राजस्व अभिलेखों में शामलात तराफ, पट्टी, पन्ना और थोला के रूप में वर्णित भूमि और राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्रामसमुदाय या उसके किसी भाग के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है;

(4) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 3 के क्लौ एसई (एमएमएम) में परिभाषित सभा क्षेत्र के भीतर स्थित सड़क, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों, पीने के कुओं या तालाबों सहित ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली या आरक्षित भूमि, जिसमें विगत पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत एक गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि शामिल नहीं है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) में से जो प्रबंधन और नियंत्रण उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23-क के अधीन राज्य सरकार में निहित है; और

(4क) आबादी देह या गोराह देह में स्थित खाली भूमि जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व न हो;

(5) बंजार कादिम के रूप में वर्णित किसी भी गांव में भूमि औरराजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के आम पु के लिए उपयोग किया जाता है:

बशर्ते कि गांव के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक शामलात देह गांव में मौजूद न हो;

लेकिन भूमि शामिल नहीं है जो-

(1) सेवा मेरे (ix) xxx xxx xxx xxx"

(17) उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि शामलात देह की परिभाषा राजस्व अभिलेखों में वर्णित भूमि को शामिल करने के साथ शुरू होती है जैसा कि उप-खंड (1) से (5) में प्रदान किया गया है। उपखंड (5) के पश्चात्, परंतुक रखा गया है। प्रावधान के बाद,उन जमीनों का बहिष्करण शुरू होता है जो शामलात देह में शामिल नहीं हैं।

(18) एक परंतुक और एक अपवाद के बीच निरुत्साहन है। एक परंतुक एक अधिनियमन खंड का अनुसरण करता है और इसे कुछ निर्दिष्ट मामलों / परिस्थितियों में अर्हता प्राप्त करता है जबकि एक अपवाद अधिनियमित खंड का एक हिस्सा है औरसामान्य अनुप्रयोग का है और इस प्रकार, कुछ छूट देता है जो अन्यथा क़ानून के सामान्य शब्दों के दायरे में आएगा। परन्तुक का सामान्य कार्य अधिनियमन से बाहर की किसी बात को छोड़कर या उसमें अधिनियमित किसी बात को अर्हता प्राप्त करना है, जो परन्तुक के लिए, अधिनियमन के दायरे में होगा। परंतुक की भाषा, भले ही वह सामान्य प्रतीत होती हो, आमतौर पर उस विषय वस्तु के संबंध में मानी जाती है जिसमें परंतुक संलग्न है। यह उस प्रावधान के अपवाद को नहीं बनाता है जिसके लिए इसे एक परंतुक के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, आम तौर पर एक परंतुक प्रावधान या खंड से परे यात्रा नहीं करता है जिसके लिए यह एक परंतुक है।

(19) धारा 2 (छ) शामलात देह को उप-खंड (1) से (5) में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणियों को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। तत्पश्चात्, उपखंड (5) में इस आशय का परंतुक जोड़ा जाता है कि गांव के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 25% गांव में मौजूद नहीं है। यदि यह परंतुक सभी उपखंडों पर लागू होता, तो इसे अपवर्जन खंडों में शामिल किया गया होता जो धारा में परंतुक का अनुसरण करता है।

(20) 1991 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 (बी), विधानमंडल के इरादे को सामने लाती है और सील करती है जो इस प्रकार है: -

(21) **1961 के पंजाब अधिनियम 18 की** धारा 2 का संशोधन- पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम कहा जाता है) की धारा 2 के खंड (छ) में, -

(a) xxx xxxx xxxx xxxx

(b) उप-क्लॉस्क (5) के परंतुक का लोप किया जाएगा;"

(21) इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि 1961 के अधिनियम में शामिल परंतुक केवल धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के लिए था।

(22) यह विवाद में नहीं है कि भूमि शामलात देह के डेल्निशन के भीतर आती है और **सुखदव सीघ और अन्य** *(सुप्रा)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, जमाबंदी में प्रविष्टि कि भूमि शामलात देह है, लेकिन खेवट में संबंधित हिस्से के अनुसार मालिकों के कब्जे में भूमि की प्रकृति से विचलित नहीं होती है और भूमि का चरित्र शामलात रहता है देह। शिव **चरण सिंह के मामले** (*सुप्रा*) और **तेल राम** और अन्य *बनाम* **ग्राम सभा मानकपुर** और अन्य, (8) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना है कि धारा 2 (जी) के सभी उप-खंड एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह से प्रत्येक अन्य के दायरे को नियंत्रित या सीमित नहीं करते हैं। यह अधिनियम की धारा 2 (जी) के केवल उप-खंड (5) पर लागू होने वाले परंतुक के संबंध में हमारे द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को और मजबूत करता है।

(23) इस प्रकार, यह माना जाता है कि परंतुक केवल 1961 एसीटी की धारा 2 (जी) के उप-क्लॉज (5) पर लागू होता हैऔर 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के उप-खंड (1) से (4) पर नहीं। प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

प्रश्न 2 और 3 के उत्तर :

(24) **ग्राम सभा सलीना के मामले** *(सुप्रा)* में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने पंजाब के मामले में इन सवालों से निपटने के दौरानपैरा 9 में निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"9. तब अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया था कि 1976 के अधिनियम संख्या 19 द्वारा, अधिनियम की धारा 2 (जी) (5) के परंतुक को हटा दिया गया है। यह भी आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय को आयुक्त के आदेश को रद्द करने के लिए कानून में इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 19 को 15 अप्रैल, 1976 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19976 में प्रकाशित हुआ।

27 अप्रैल, 1976 को सरकारी राजपत्र। इसे प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। 1976 का संशोधन अधिनियम संख्या 19 आयुक्त द्वारा मामले के निर्णय के बाद लागू हुआ अधिनियम की धारा 7 के तहत आवेदन के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी और अंत में संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले उन लोगों को तय करने के लिए सशक्त मंच के उच्चतम स्तर तक निर्णय लिया गया था, अर्थात, आयुक्त। हालांकि, इली रिट याचिका उस दिन लंबित थी जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। पार्टियों के वकील इस बात से सहमत हैं कि 1976 का अधिनियम संख्या 19 संचालन में पूर्वव्यापी नहीं था। उच्च न्यायालय कानून में बदलाव का नोटिस केवल तभी ले सकता था जब कार्यवाही राजस्व अधिकारियों द्वारा तय की गई प्रक्रिया की निरंतरता में थी। अधिनियम की धारा 7 केवल दो अपील प्रदान करती है; एक कलेक्टर को और दूसरा आयुक्त को। यह आगे कोई अपील या संशोधन प्रदान नहीं करता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत आयुक्त का आदेश अंतिम है। इसलिए, अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई और 23 अप्रैल, 1976 को अंतिम रूप प्राप्त हुई, जब आयुक्त ने प्रतिवादी नंबर 1 की अपील स्वीकार कर ली। अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारियों के पदानुक्रम में, उच्च न्यायालय कोईआंकड़ा नहीं करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इसके समक्ष कार्यवाही अधिनियम के तहत कार्यवाही की निरंतरता में नहीं है। यह केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है कि उच्च न्यायालय, अपने असाधारण नागरिक अधिकार क्षेत्र के तहत, यह जांच करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है कि क्या न्यायालय या ट्रिब्यूनल या किसी प्राधिकरण के समक्ष निर्णय या कार्यवाही को खड़े होने की अनुमति दी जानी चाहिए या न्याय की कमी के कारण या रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के कारण, अलग रखा जाना चाहिए। इस क्षेत्राधिकार के दौरान, उच्च न्यायालय उन अधिकारियों के आदेश के खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं सुनता है जिनके आदेश या कार्यवाही की वह जांच करता है। इस प्रकार यह मूल कार्यवाही की निरंतरता नहीं है। इस कारण से, उच्च न्यायालयआयुक्त के निर्णय को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 2 (जी) (5) के परंतुक के निरसन के प्रस्ताव को विचार में नहीं ले सकता है। (महत्व हमारे द्वारा आपूर्ति)

(25) उपर्युक्त निर्णय का अनुपात यह है कि अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष कार्यवाही मूल कार्यवाहीको जारी रखने के लिए होगी और राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान अधिनियम में संशोधन को ध्यान में रखा जा सकता है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस पर प्रभाव दिया जा सकता है।

(26) यह विवाद में नहीं है कि 1961 अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इसका अवलोकन करने से पता चलता है कि आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है। यदि क़ानून किसी भी सीमा के लिए प्रदान नहीं करता है, तो न्यायालय ऐसी अवधि को अपने दम पर आयात नहीं कर सकता है। आयुक्त अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान मामले में, कलेक्टर द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 1988 के आदेश के पारित होने के बाद, ग्राम पंचायत द्वारा 2 1 जुलाई, 1989 को संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी, आयुक्त द्वारा इसका मनोरंजन बिना किसी अधिकार क्षेत्र के सीमाओं या शक्तियों के प्रयोग से परे नहीं कहा जा सकता है।

का उपयोग कर सकते हैं

(27) 1961 के अधिनियम की धारा 13 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। अधिनियम की धारा 13-क किसी व्यक्ति या पंचायत को, जो इस अधिनियम के अधीन पंचायत में निहित या निहित समझी गई किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित का दावा करती है, यह अधिकार देती है कि वह इस बारे में न्यायनिर्णयन के लिए वाद दायर कर सकता है कि क्या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति शालत देह नहीं है और क्या कोई भूमि या अन्य अचल

संपत्ति या कोई अधिकार/शीर्षक या हित उसमें निहित है या इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित नहीं है। मुकदमा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसमें उस क्षेत्र में न्यायशास्त्रहै जिसमें ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्तियां स्थित हैं। धारा 13-बी में अपील और पुनरीक्षण का प्रावधान है। यह खंड मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है: -

"13-ख. अपील और पुनरीक्षण-

(1) प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत पारित आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, कलेक्टर को ऐसे रूप और तरीके से एक अपीलकर्ता पसंद कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और कलेक्टर अपील सुनने के बाद कर सकता है, पुष्टि करें, बहुत या आदेश को उलट दें जैसा कि वह उचित समझता है:

बशर्ते कि ऐसी कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि धारा 7 की उपधारा (2) के तहत लगाए गए दंड की राशि, यदि कोई हो, कोलेक के पास जमा नहीं की जाती है।

(2) आयुक्त, कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के रिकॉर्ड या उसके द्वारा पारित आदेश के लिए स्वतः संज्ञान ले सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

अधिनियम की धारा 13-बी (1)कलेक्टर के समक्ष आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर 1961 अधिनियम की धारा 13-ए के तहत पारित आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अपील का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 13-बी (2) आयुक्त में शक्तियां निहित करती है जो प्रकृति में पुनरीक्षण हैं।

(28) इस प्रकार, उपरोक्त के पठन से यह प्रकट होता है कि आयुक्त को कार्यवाही या आदेश कीवैधता या औचित्य के संबंध में संतुष्ट करने के लिए उसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या उसके समक्ष लंबित कार्यवाही के रिकॉर्ड मांगने की शक्तियां प्रदान की गई थीं और आगे इस संबंध में ऐसा आदेश पारित करने की शक्तियां प्रदान की गई थींजैसा कि वह उचित समझे। इसके साथ जुड़ा एकमात्र राइडर यह है कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, आयुक्त के समक्ष कार्यवाही1961 अधिनियम की धारा 13-ए के तहत पसंद किए गए मुकदमे की निरंतरता में होगी।

(29) अधिनियम की धारा 13-ग इस प्रकार है-

"13ग) आदेशों की अंतिमता--इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, प्रथम श्रेणी के सहायक समाहर्ता, कलेक्टर या आयुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(30) यह प्रावधान किसी भी तरह का संदेह नहीं छोड़ता है कि मूल कार्यवाही तब तक जारी रहती है जब तक कि यह धारा 13-सी के तहत प्रदान की गई अंतिम तिथि प्राप्त नहीं करलेती। इस प्रकार, 1961 अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही मूल कार्यवाही की निरंतरता होगी। 1961 के अधिनियम में संशोधन लाया गया था

11 फरवरी, 1992 को 1991 संशोधन अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य के बारे में। 1991 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 (बी) के *तहत*, उप खंड (5) के परंतुक कोहटा दिया गया है। **ग्राम सभा सलीना के मामले** में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात को देखते हुए, राजस्व प्राधिकारी द्वारा इसे नोट किया जा सकता है, जिसके समक्ष संशोधन किए जाने के समय संविधि के समक्ष कार्यवाही लंबित थी। वर्तमान मामले में, जब 1961 के अधिनियम में संशोधन किया गया था तब पुनरीक्षण आयुक्त के समक्ष लंबित था। आयुक्त--1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 और 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2069 में दिनांक 23 जुलाई, 1992 के आदेश द्वारा संशोधन का निर्णय करते समय 1961 के अधिनियम में संशोधन पर सही ध्यान दिया गया है। **बचना** *उर्फ* **बचन सिंह के मामले** *(सुप्रा)* में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ फायदेमंद होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कानून में बदलाव को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है।

(31) श्री सरीन, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क, कि बाद के खरीदारों के निहित अधिकारों को अधिनियम के संशोधन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, जब उक्त अधिनियम संचालन में भावी है, के साथ विवादित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इस तथ्य के आलोक में कि गांव के मालिकों के बाद के खरीददारों ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपने जूते में कदम रखा है, वे विक्रेताओं की तुलना में बेहतर अधिकार या शीर्षक का दावा नहीं कर सकते हैं और इसलिए, उन्हें तैरना होगा या उनके साथ डूबना होगा। आयुक्त अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए भी उसके समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कानून में बदलाव को ध्यान में रख सकता है और इसलिए, अधिनियम में लाया गया संशोधन आयुक्त द्वारा अपने 23 जुलाई, 1992 के आदेश द्वारा उचित रूप से प्रभावी किया गया है और आयुक्त द्वारा शक्ति के ऐसे प्रयोग में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(32) प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर यह है कि 1961 के अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही मूल वाद की निरंतरता है। धारा 2 (जी) में संशोधन पुनरीक्षण कार्यवाही पर लागू होगा और चूंकि यह मूल कार्यवाही की निरंतरता है, इसलिए बाद के खरीदार के निहित अधिकार, यदि कोई हो, *आईआईएस-पेंडेंस* के सिद्धांत से प्रभावित होंगे क्योंकि वे मूल भूमि मालिकों यानी गांव के मालिकों की तुलना में बेल्टर शीर्षक का दावा नहीं कर सकते हैं।

(33) . श्री सरीन के पास था। बहुत निष्पक्ष रूप से और मामले की दलीलों को खोलते हुए शुरुआत में, कहा कि मालिकों और बाद के खरीदारों का दावा परंतुक पर निर्भर था जो 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के बाद उल्लेख करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि यदि यह वह है कि परंतुक धारा 2 (जी) उप-खंड (1) से (5) पर लागू होता है, तो मालिक और बाद के खरीदार 1961 अधिनियम की धारा 13-ए के तहत उनके द्वारा दायर मुकदमे में उनके द्वारा किए गए दावे के हकदार होंगे और यदि यह माना जाता है कि पी रोविसो केवल धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) पर लागू होताहै, मालिक और बाद के खरीदार उनके द्वारा दावा किए गए लाभ के हकदार नहीं होंगे। चूंकि हमने माना है कि परंतुक केवल धारा 2 (जी) के उप-खंड (5) के लिए था, इसलिए प्रोपराइटरऔर बाद के खरीदार किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, वे इस कारण से किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे कि धारा 2 (जी) में संशोधन जो क़ानून के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लागू हुआ था, इन कार्यवाहियों पर लागू होगा क्योंकि यह मूल कार्यवाही की निरंतरता है। ऐसा होने के कारण, धारा 2 (जी) के उप-क्लॉज (5) के परंतुक, जो 1961 के अधिनियम के संशोधन से पहले मौजूद थे, को 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इस प्रकार, बाद के खरीदारों या मूल भूमि मालिकों का कोई दावा जीवित नहीं है क्योंकि उन्होंने न केवल इस प्रावधान पर अपना दावा किया था, बल्कि यह अकेले इस पर निर्भर था।

(34) उपरोक्त के मद्देनजर, 1989 के सीडब्ल्यूपी संख्या 10381 में कमीशन मिशनर, गुड़गांव डिवीजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1992 (अनुलग्नक पी -7) को बरकरार रखा जाता है और आयुक्त (अपील), अंबाला डिवीजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1989 (अनुलग्नक पी - 3) सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 और 1996 के 2069 में पारित किया जाता है।

(35) 5) नतीजतन, 1989 की सीडब्ल्यूपी संख्या 103 81 की अनुमति दी जाती है जबकि 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11821 और 1996 की 2069 को खारिज कर दिया जाता है।

(36) इस आदेश की एक फोटोकॉपी प्रत्येक जुड़े मामले की फाइल पर रखी जाए।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारि क औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम